

अथवा

मनीषा पवार  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक,  
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-1

देहरादून दिनांक 07 मई, 2009

**विषय** चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक में समाज कल्याण विभाग के नागरिक अधिकार (संरक्षण) 1956 के क्रियान्वयन हेतु अनुदान संख्या-30 के आयोजनागत पक्ष के विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशियों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 205/XXVII(1)/2009 दिनांक 25 मार्च, 2009 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 (01 अप्रैल 2009 से 31 जुलाई 2009 तक) के आय व्ययक में नागरिक अधिकार (संरक्षण) 1956 के क्रियान्वयन हेतु अनुदान संख्या-30 के आयोजनागत पक्ष की विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशियों में से सलगनक के अनुदान वचनपत्र/आवश्यक मदों में रुपये 15,00,000/- (रुपये पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में वित्त विभाग के उक्त शासनादेश में उल्लेखित एवं निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके नियंत्रण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 205/XXVII(1)/2008 दिनांक 25 मार्च, 2008 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. आयोजनागत/आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित अन्य धनराशियों हेतु निम्नानुसार मांग प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्बन्धित व्यय की फंडिंग (ग्रैन्ट्स के अन्तर्गत) पर अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर केंद्रस्थलों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
4. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
5. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त बुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सहाय अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
6. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख/तघु/उप तथा विस्तृत जीर्णक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दहिनी और लाल स्थाही से अनुदान संख्या-30 तथा आयोजनेत्तर शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महासंचालक, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
7. सलगनक में वर्णित धनराशियों का समय से उपबोध करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि प्रतिष्ठित अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

8. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त मुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय-सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
10. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
11. सनस्त चालू निर्माण कार्य, नए निर्माण कार्य, उपकरण व संयंत्र का क्रय, वाहन का क्रय एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय की स्वीकृतियों के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को पृथक् से उपलब्ध कराए।
12. बी०एम०-13 पर संकलित मासिक व्यय की चुनारें नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
13. छठे वेतन आयोग की संस्तुति के लागू होने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2009-10 में देय 30 प्रतिशत एरियर की धनराशि, जो कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि खाते में डाली जानी है, का भुगतान 01 अप्रैल, 2009 से 31 जुलाई, 2009 तक के लेखानुदान द्वारा प्राविधानित धनराशि से नहीं किया जायेगा। तथा वित्तीय वर्ष 2008-09 में देय 40 प्रतिशत वेतन एवं भत्तों के एरियर की धनराशि यदि किसी कारण वश सामान्य भविष्य निधि खाते में नहीं डाली जा सकी हो तो उसका भुगतान भी माह जुलाई, 2009 के बाद ही किया जायेगा। यह प्रतिबन्ध सेवानिवृत्त होने वाले अथवा अन्य कारणों से सेवा में बने न रहने वाले कर्मिकों के सम्बन्ध में नहीं रहेगा।
14. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रावधानित रुका 2008, वित्तीय नियम संहिता खण्ड -1 (वित्तीय ऑडिटल प्रक्रियागत नियम) वित्तीय नियम संहिता खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम) भाग-1(व्यय सम्बन्धी नियम) (वज्रत मेनुअल) तथा अन्य चुनारा नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
15. यह ज्ञात/अज्ञात है कि शराव व अरु व निषेधित पदार्थों का अनुपालन आवश्यक है। अतः व्यय करते समय निषेधितता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
16. इस संहिता में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-30 के अंतर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की चुनगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।
17. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 41(P)/XXVIII(1)/2009 दिनांक 28 अप्रैल 2009 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीया,  
  
 ( मनीषा पंवार )  
 सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: संख्या:-386/XVII-1/2009-10(39)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव-मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव मा० समाज कल्याण मंत्री उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव-मुख्य सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. त्रिस्त कोषाधिकारी हल्द्वानी-नैनीताल।
9. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03 उत्तराखण्ड शासन।
12. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून।
13. बजट, राजकोषीय निर्माण एवं ससाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. आदेश पत्रिका।

आज्ञा से  
(धीरेन्द्र सिंह देताल)  
उप सचिव।

शासनादेश संख्या-36/XVII-1/2009-10(39)/2009,  
दिनांक 07 मई, 2009 का संलग्नक

अनुदान संख्या-30

आयोजनागत

मतदेय

लेखाशीर्षक :

2225-01-800-08-00

मुख्य शीर्षक :

2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण।

उप मुख्य शीर्षक :

01-अनुसूचित जातियों का कल्याण।

अन्तः शीर्षक :

800- अन्य व्यय।

उप शीर्षक :

08- नागरिक अधिकार (संरक्षण) अधिनियम 1956 का क्रियान्वयन।

व्यवहार शीर्षक :

00-

(धनराशि हजार रुपये में)

मानक मद	आवृत्ति धनराशि
20- सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	1433
42- अन्य व्यय	67
योग	1500

(रुपये पन्द्रह लाख मात्र)

(धीरेन्द्र सिंह दताल )  
उप सचिव।